



राजपत्र, हिमाचल प्रदेश

(असाधारण)

हिमाचल प्रदेश राज्य शासन द्वारा प्रकाशित

शिमला, शुक्रवार, 13 जुलाई, 1990/22 आषाढ़, 1912

हिमाचल प्रदेश सरकार

विधि विभाग

अधिसूचना

शिमला, 13 जुलाई, 1990

क्रमांक एल० एल० आर०-डी (6)8/9०-लैजिस्लेशन.—हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल, भारत के संविधान के अनुच्छेद 213 के खण्ड (1) के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, तारीख 13 जुलाई, 1990 को प्रख्यापित

विद्युत (प्रदाय) (हिमाचल प्रदेश संशोधन) अध्यादेश, 1990 (1990 का अध्यादेश संख्यांक 2) संविधान के अनुच्छेद 348 (3) के अधीन उसके प्राधिकृत पाठ सहित, हिमाचल प्रदेश, राजपत्र में प्रकाशित करते हैं।

आदेश द्वारा,
राज कुमार महाजन,
सचिव (विधि)

1990 का हिमाचल प्रदेश अध्यादेश संख्यांक 2.

विद्युत (प्रदाय) (हिमाचल प्रदेश संशोधन) अध्यादेश, 1990

भारत गणराज्य के इकतालीसवें वर्ष में हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल द्वारा प्रख्यापित।

विद्युत (प्रदाय) अधिनियम, 1948 (1948 का केन्द्रीय अधिनियम सं० 54) का, जहां तक यह हिमाचल प्रदेश राज्य में लागू है, संशोधन करने के लिए अध्यादेश;

चूंकि हिमाचल प्रदेश राज्य विद्युत बोर्ड के सदस्यों की सेवा निवृत्ति की आयु को निर्धारित करने हेतु प्रावधान करना आवश्यक समझा गया है;

और चूंकि हिमाचल प्रदेश विधान सभा सत्र में नहीं है और राज्यपाल का समाधान हो गया है कि ऐसी परिस्थितियां विद्यमान हैं जिन के कारण तुरन्त कार्रवाई करना उनके लिए आवश्यक हो गया है;

और अध्यादेश को प्रख्यापित करने के लिए भारत के राष्ट्रपति के अनुदेश और पूर्व अनुमोदन अभिप्राप्त कर लिया गया है;

अतः अब हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल, भारत के संविधान के अनुच्छेद 213 के खण्ड (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए निम्नलिखित अध्यादेश प्रख्यापित करते हैं:—

1. इस अध्यादेश का संक्षिप्त नाम विद्युत (प्रदाय) (हिमाचल प्रदेश संशोधन) अध्यादेश, 1990 है। संक्षिप्त नाम।
2. विद्युत (प्रदाय) अधिनियम, 1948 की धारा 5 की उप-धारा (6) में आए शब्दों "कोई व्यक्ति" के पश्चात् "जिसने पैंसठ वर्ष की आयु प्राप्त कर ली है या" शब्द अन्तःस्थापित किए जाएंगे। धारा 5 का संशोधन।
3. (1) विद्युत (प्रदाय) अधिनियम, 1948, या तद्धीन बनाए गए नियमों, विनियमों या उपविधियों के किन्हीं उपबन्धों में या न्यायालय के किसी निर्णय, डिक्री या आदेश अथवा किसी संविदा में किसी बात के प्रतिकूल होते हुए भी, विद्युत (प्रदाय) (हिमाचल प्रदेश संशोधन) अध्यादेश, 1990 के प्रारम्भ से पूर्व की गई कोई ऐसी नियुक्ति जिसके द्वारा किसी व्यक्ति को पैंसठ वर्ष की आयु प्राप्त करने के पश्चात् भी बोर्ड का सदस्य बने रहने का अधिकार प्राप्त है, शून्य होगी; और ऐसे प्रारम्भ पर यह समझा जाएगा कि वह बोर्ड का सदस्य नहीं रहा है। कतिपय नियुक्तियों का शून्य होना।

(2) उप-धारा (1) के अधीन बोर्ड के सदस्य के पद पर न रहने पर, ऐसा सदस्य प्रतिपूर्ति के लिए हकदार होगा जैसी राज्य सरकार द्वारा अवधारित की जाये; किन्तु ऐसी प्रतिपूर्ति उसकी अनवसित पदावधि के लिए उसे संदेय वेतन और भत्तों की रकम के बराबर की रकम से अधिक नहीं होगी।

शिमला:
13 जुलाई, 1990.

बी० रचैया,
राज्यपाल।

राज कुमार महाजन,
सचिव (विधि)।

AUTHORITATIVE ENGLISH TEXT

H. P. Ordinance No 2 of 1990.

THE ELECTRICITY (SUPPLY) (HIMACHAL PRADESH AMENDMENT) ORDINANCE, 1990

Promulgated by the Governor of Himachal Pradesh in the forty-first year of the Republic of India.

An Ordinance to amend the Electricity (Supply) Act, 1948 (Central Act No. 54 of 1948) in its application to the State of Himachal Pradesh.

Whereas it is considered necessary to make provision of providing an age of superannuation for the members of the Himachal Pradesh State Electricity Board ;

And whereas the Legislative Assembly of the State of Himachal Pradesh is not in Session and the Governor is satisfied that circumstances exist which render it necessary for him to take immediate action ;

And whereas instructions and prior approval of the President of India to promulgate the Ordinance have been obtained ;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by clause (1) of Article 213 of the Constitution of India, the Governor of Himachal Pradesh is pleased to promulgate the following Ordinance:—

Short title.

1. This Ordinance may be called the Electricity (Supply) (Himachal Pradesh Amendment) Ordinance, 1990.

Amendment of Section 5.

2. In sub-section (6) of section 5 of the Electricity (Supply) Act, 1948, for the words "if he is a member of Parliament", the words "if he has attained the age of 65 years or is a member of Parliament" shall be substituted.

Certain appointments to be void

3. (1) Notwithstanding anything to the contrary contained in any provisions of the Electricity (Supply) Act, 1948, rules, regulations or bye-laws made thereunder or in any judgement, decree or order of the court or in any contract, any appointment, made before the commencement of the Electricity (Supply) (Himachal Pradesh Amendment) Ordinance, 1990, whereby a person has a right to continue as a member of the Board after attaining the age of 65 years, shall be void; and no such commencement he shall be deemed to have ceased to hold office of the member of the Board.

(2) On ceasing to hold office of the member of the Board under sub-section (1), such member shall be entitled to compensation as may be determined by the State Government; but such compensation shall not exceed the amount equivalent to the amount of salary and allowances payable to him for his unexpired term.

SHIMLA :
the 13th July, 1990.

B. RACHAIAH,
Governor.